TRANSPORT (a) and (b) Central assistance is given to the States in the form of block loans and grants and is not tied to any particular project. Outlay for irrigation sector of the State Government during VII Plan was Rs. 317 crores, against which the anticipated expenditure is Rs. 340 crores. Besides this, Central assistance has also been given to the State Government during Vill Plan as under: —

(1) Assistance under irrigation advancement programme

(a) Major and Medium Projects. . . . Rs. *6-16* croresj

(b) Stabilisation of Tanks..... Rs. 3-20 croresj

(2) Assistance for Command Area Development Programme Rs. 18-86 croresj

(3) Assistance for Minor Irrigation Programme .. Rs. 3-95 crores

An additional irrigation potential of 188 th. ha. is anticipated to have been created in the State through Major and Medium and Minor Irrigation Schemes the VII Plan.

उत्तर प्रदेश में प्रदूषण निवारक कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि

748. **कुमारी आलिया :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रदूषण निवारक कार्यक्रमों पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) बिना खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है और इस राशि को खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में किये गये कार्य का वर्ष वार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए 66.28 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई । इसमें 50.24 लाख रुपये खर्च किए गए ।

(ख) नीचे दिए गए कार्यक्रमों में 16.04 लाख रुपये खर्च नहीं किए गए:–

(1) केन्द्र-राज्य समन्वित कार्यक्रम

(I) कर्मचारियों के लिए 1.69 लाख रु0

(II) उपकरणों के लिए 0.64 लाख रु0

(2) पर्यावरण नीति और कानून

(I) प्रयोगशाला कर्मचारियों के लिए 2.31 लाख रु0

(II) उपकरणों के लिए 10.75 लाख रु0

(III) खतरनाक पदार्थों का प्रबन्ध कर्मचारियों और उपकरणों के लिए 0.75 लाख रु0

राज्य में भर्ती पर पाबन्दी के कारण कर्मचारियों के लिए निर्धारित राशि खर्च नहीं की जा सकी ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए :—

(1) राज्य में कुल 12000 उद्योगों में से 1700 उद्योगों की जल प्रदूषक इकाइयों के रूप में पहचान की गई । 285 उद्योगों ने पहले बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा लिए हैं और 500 इकाइयों में बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने का कार्य चल रहा है ।

(2) प्रदूषण नियंत्रण की जांच के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ने उद्योगों और नदियों से 30,000 नमूने इकट्ठे किए गए हैं, शोधन के पश्चात् इकट्ठा किए गए बहिस्रावों की निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए जांच की गई।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ने दोषी इकाइयों के विरुद्ध 165 मामले दर्ज किए हैं।

स्वचालित टेलीफोन प्रणाली

749. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन नगरों में स्वचालित टेलीफोन प्रणाली की व्यवस्था है; और

(ख) अगले एक वर्ष के दौरान इस प्रणाली के विस्तार की क्या योजना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री और संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) शहरों के नाम **विवरण** में दिए गए हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान देश में इस प्रणाली की स्विचिंग क्षमता को 9.5 लाख लाइनों तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है बशर्ते कि समय पर उपस्कर उपलब्ध हों।

विवरण

उन शहरों के नाम जहां पर आटोमेटिक टेलीफोन प्रणाली है।

क्रम सं.	राज्य/जिला/शहर
	आंध्र प्रदेश
1.	हैदराबाद
2.	विजयवाड़ा
3.	अदोनी
4.	अनन्तपुर
5.	भीमावरम
6.	कुडापाह
7.	इलुरू
8	गुन्टूर
9.	काकीनाडा
10.	कुरनूल
11.	मच्छलीपतनम
12.	तेल्लूर
13.	निजामाबाद
14.	परोद्दारतर
15.	राजमुन्दरी
16.	तेनाली
17.	तिरुपती
18.	विशाखापत्तनम
19.	विजयनगरम
20.	वारंगल
	असम
1.	गुवहाटी
	बिहार
1.	पटना
2.	आरा
3.	बिहारशरीफ
4.	चास और बोकारो
5.	स्टील सिटी
6.	भागलपुर
7.	छपरा
8.	दरभंगा
9.	धनबाद
10.	गया
11.	जमशेदपुर
12.	कटिहार
13.	मुजफ्फरपुर
14.	मुंगेर
15.	पूर्णिया
16	रांची